



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-02122024-259094
CG-TN-E-02122024-259094

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 960]
No. 960]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2024/अग्रहायण 11, 1946
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2024/AGRAHAYANA 11, 1946

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

अधिसूचना

चेन्नै, 2 दिसम्बर, 2024

फा. सं. HRMD/SUP/177/01/2024-25.—बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के बाद और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के पत्र संख्या 4/2/2015-IR, दिनांकित 18 दिसंबर, 2020 के अनुसरण में किए गए या न किए गए कार्यों को छोड़कर, 1 नवंबर, 2017 से इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि तक, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करने के लिए यहां विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. (1) इन विनियमों को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये उस तिथि से प्रभावी होंगे जिस दिन इन्हें आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

2. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (जिसे बाद में "कथित विनियमन" कहा जाएगा) में, विनियम 3 में-

(i) खंड (फ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

'(फ) "परिवार", चिकित्सा सुविधाओं और अवकाश किराया रियायत के उद्देश्य से, अधिकारी के जीवनसाथी, पूरी तरह से निर्भर अविवाहित बच्चे (जिसमें सौतेले बच्चे और कानूनी रूप से दत्तक बच्चे शामिल हैं), शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग भाई या बहन जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, विधवा बेटियां और निर्भर तलाकशुदा या अलग हुई बेटियां, बहनें (अविवाहित, तलाकशुदा, पति द्वारा त्यागी गई, या विधवा बहनें) और माता-पिता जो अधिकारी पर पूरी तरह निर्भर हैं।

व्याख्या 1 – इस खंड के उद्देश्यों के लिए-

(i) "पूरी तरह निर्भर पारिवारिक सदस्य" का अर्थ होगा ऐसा पारिवारिक सदस्य जिसकी आय ₹12,000/- प्रति माह से अधिक न हो, और यदि माता-पिता में से किसी एक की आय ₹12,000/- प्रति माह से अधिक हो या दोनों माता-पिता की संयुक्त आय ₹12,000/- प्रति माह से अधिक हो, तो दोनों माता-पिता को अधिकारी पर पूरी तरह निर्भर नहीं माना जाएगा; और

(ii) एक विवाहित महिला अधिकारी अपने प्राकृतिक माता-पिता या ससुराल पक्ष के माता-पिता को परिवार की परिभाषा में शामिल कर सकती है, लेकिन दोनों को नहीं, बशर्ते कि ऐसे माता-पिता या ससुराल के माता-पिता उस पर पूरी तरह निर्भर हों।

व्याख्या 2 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना के उद्देश्य से, सभी अधिकारियों (पुरुष या महिला) के लिए, निर्भर माता-पिता या ससुराल पक्ष के माता-पिता में से कोई भी दो शामिल किए जाएंगे, और अधिकारी को इन निर्भर व्यक्तियों में से किसी एक या दोनों को बदलने का विकल्प होगा।

व्याख्या 3 - किसी अधिकारी के शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे आयु या वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना, आय मापदंडों के अधीन, निर्भर माने जाएंगे।';

(ii) खंड (i) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(i) "प्रबंध निदेशक" का अर्थ बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी है।"

3. कथित विनियमों के विनियम 4 में-

(a) उप-विनियम (6) में, व्याख्या को हटा दिया जाएगा;

(b) उप-विनियम (7) और (8) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

(7) 1 नवंबर, 2017 से, प्रत्येक ग्रेड के लिए वेतनमान इस प्रकार होगा:

(क) शीर्ष कार्यपालक ग्रेड

- स्केल VII = ₹116120 – 3220/4 – 129000
- स्केल VI = ₹104240 – 2970/4 – 116120

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

- स्केल V = ₹89890 – 2500/2 – 94890 – 2730/2 – 100350
- स्केल IV = ₹76010 – 2220/4 – 84890 – 2500/2 – 89890

(ग) मध्य प्रबंधन ग्रेड

- स्केल III = ₹63840 – 1990/5 – 73790 – 2220/2 – 78230
- स्केल II = ₹48170 – 1740/1 – 49910 – 1990/10 – 69810

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

- स्केल I = ₹36000 – 1490/7 – 46430 – 1740/2 – 49910 – 1990/7 – 63840

व्याख्या:

हर वह अधिकारी जो 31 अक्टूबर, 2017 को लागू वेतनमान के तहत शासित है, उसे 1 नवंबर, 2017 को इस उप-विनियम में निर्धारित वेतनमान में पहले चरण से प्रारंभ होकर क्रमशः उसी चरण के आधार पर फिट किया जाएगा। वेतनवृद्धि की तारीख पूर्ववत् उसी वार्षिक तिथि पर होगी, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

(8) उप-विनियम (1) से (7) में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो यह अपेक्षा करता हो कि बैंक में हमेशा इन सभी ग्रेडों में अधिकारी कार्यरत हों।

(9) (क) 1 नवंबर, 2012 से, अधिकारियों को विशेष भत्ते निम्नलिखित अनुसार दिए जाएंगे:

- स्केल I-III - मूल वेतन का 7.75% और उस पर लागू महंगाई भत्ता
- स्केल IV-V - मूल वेतन का 10% और उस पर लागू महंगाई भत्ता
- स्केल VI-VII - मूल वेतन का 11% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

(ख) 1 नवंबर, 2017 से, अधिकारियों को विशेष भत्ते निम्नलिखित के अनुसार प्रदान किए जाएंगे:

- स्केल I-III - मूल वेतन का 16.40% और उस पर लागू महंगाई भत्ता
- स्केल IV-V - मूल वेतन का 19% और उस पर लागू महंगाई भत्ता
- स्केल VI-VII - मूल वेतन का 20% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

व्याख्या: खंड (a) और (b) में उल्लिखित विशेष भत्ते और उस पर लागू महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन (नई पेंशन योजना सहित), भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के लिए मान्य नहीं होंगे।

4. कथित विनियमों के विनियम 5 में-

(अ) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(1) विनियम 4 के उप-विनियम (7) के प्रावधानों के अधीन, 1 नवंबर, 2017 से, वेतनवृद्धि निम्नलिखित के अनुसार प्रदान की जाएगी:

(क) उप-विनियम 4 के उप-विनियम (7) में निर्दिष्ट वेतनमान में निर्धारित वेतनवृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन, वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी और जिस महीने में वेतनवृद्धि देय हो, उस महीने के पहले दिन दी जाएगी।

(ख) स्केल I और स्केल II के अधिकारियों को अपने संबंधित स्केल के अधिकतम वेतन तक पहुंचने के एक वर्ष बाद, अगले उच्चतर स्केल में आगे की वेतनवृद्धि (गतिरोध वेतनवृद्धि सहित) प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि वे दक्षता सीमा को पार कर लें।

(ग) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल I में अधिकारी, जो उप-खंड (b) के तहत मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II के वेतनमान में आ गए हैं, उच्चतर स्केल के अधिकतम वेतन तक पहुंचने के बाद, उन्हें प्रत्येक दो पूरे वर्षों की सेवा के लिए पांच गतिरोध वेतनवृद्धियां मिलेंगी, जिनमें से पहले दो ₹1990/- प्रत्येक और अगली तीन ₹2220/- प्रत्येक की होंगी:

बशर्ते, अधिकारी पांचवीं गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए चौथी गतिरोध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2017, जो भी बाद में हो, के लिए पात्र होंगे।

(घ) मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II में अधिकारी, जो उप-खंड (b) के तहत मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III के वेतनमान में आ गए हैं, उच्चतर स्केल के अधिकतम वेतन तक पहुंचने के बाद, प्रत्येक दो पूरे वर्षों की सेवा के लिए ₹2220/- प्रत्येक की पांच गतिरोध वेतनवृद्धियां प्राप्त करने के पात्र होंगे:

बशर्ते, अधिकारी पांचवीं गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए चौथी गतिरोध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2017, जो भी बाद में हो, के लिए पात्र होंगे।

(ङ) जिन अधिकारियों को मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III में पदोन्नत किया गया है या जिनकी नियुक्ति इस ग्रेड में की गई है, वे छः गतिरोध वेतनवृद्धियों के पात्र होंगे, जिनमें से पहले चार ₹2220/- प्रत्येक की होंगी और प्रत्येक दो वर्षों की सेवा पूरी करने पर प्रदान की जाएगी। अगली दो ₹2500/- प्रत्येक की होंगी और चौथी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद प्रत्येक दो वर्षों की सेवा पूरी होने पर प्रदान की जाएगी:

बशर्ते, छठी गतिरोध वेतनवृद्धि पांचवीं गतिरोध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2017, जो भी बाद में हो, के लिए जारी की जाएगी।

(ii) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल IV में अधिकारी, अपने स्केल के अधिकतम वेतन तक पहुंचने के बाद, प्रत्येक दो पूरे वर्षों की सेवा के लिए दो गतिरोध वेतनवृद्धियों के पात्र होंगे। पहली गतिरोध वेतनवृद्धि ₹2500/- और दूसरी ₹2730/- की होगी:

बशर्ते, अधिकारी को पहली गतिरोध वृद्धि प्राप्त करने के दो वर्ष बाद, या 1 नवंबर, 2017 को, जो भी बाद में हो, दूसरा गतिरोध वृद्धि प्राप्त करने का पात्र होगा;

(iii) स्केल-I से स्केल-IV तक के अधिकारियों द्वारा उनके बैंक सेवा के दौरान 1 नवंबर, 2017 तक प्राप्त गतिरोध वृद्धि को, पहले की तीन वर्ष की अवधि से दो वर्ष की अवधि में पुनः समायोजित किया जाएगा, जो उनकी अधिकतम वेतन सीमा पर

पहुँचने की तारीख से प्रभावी होगा, और अधिकारी 1 नवंबर, 2017 से संशोधित अवधि के अनुसार गतिरोध वृद्धि के लिए काल्पनिक रूप से पात्र होगा, जो सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योग्य होगा:

बशर्ते, संशोधित और पुनः समायोजित गतिरोध वृद्धि की अवधि के कारण प्राप्त होने वाला मौद्रिक लाभ 1 नवंबर, 2020 से या पात्रता की वास्तविक तिथि से, जो भी बाद में हो, देय होगा।

(iv) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-V में अधिकारी अधिकतम वेतन सीमा पर पहुँचने के दो वर्ष बाद, या 1 नवंबर, 2020 को, जो भी बाद में हो, ₹2970/- की एक गतिरोध वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे:

बशर्ते, ऐसे अधिकारी, जो प्रस्तावित पदोन्नति को अस्वीकार करते हैं, उन्हें यह गतिरोध वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी।

इस उप-नियम के तहत उच्चतर स्केल में ऐसे वृद्धि का प्रदान किया जाना पदोन्नति नहीं मानी जाएगी, और अधिकारियों के विशेषाधिकार, सुविधाएं, कर्तव्य और जिम्मेदारियां उनके मौलिक पदों के अनुसार बनी रहेंगी।

(आ) उप-नियम (2) में, स्पष्टीकरण में, उपखंड (g) के प्रावधान के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाएगा, अर्थात:

"(एच) 1 नवंबर, 2017 से, अन्य सभी स्थितियां समान होने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की मात्रा निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट अनुसार संशोधित मानी जाएगी:"

तालिका

(1)	(2)
जिन्होंने जूनियर एसोसिएट ऑफ इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स भाग I पास किया है	(i) वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के एक वर्ष बाद ₹1020 प्रति माह।
जो अधिकारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के दोनों भाग उत्तीर्ण कर चुके हैं:	(क) स्केल के अधिकतम सीमा पर पहुँचने के एक वर्ष बाद प्रति माह ₹ 1020 (ख) स्केल के अधिकतम सीमा पर पहुँचने के दो वर्ष बाद प्रति माह ₹ 2550

अगर कोई अधिकारी जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (दोनों या किसी एक भाग) की योग्यता स्केल की अधिकतम सीमा पर पहुँचने के बाद प्राप्त करता है, तो उसे इस योग्यता के आधार पर पेशेवर योग्यता वेतन (Professional Qualification Pay) की पहली किस्त योग्यता प्राप्त करने की तारीख से दी जाएगी। आगे की किस्तें पहली किस्त की रिलीज की तारीख के अनुसार जारी की जाएंगी।"

(ग) उप-विनियम (3) के तहत:

(i) उप-खंड (एफ) में तालिका के बाद दिए गए नोट्स (i) से (vi) तक हटाए जाएंगे।

(ii) उप-खंड (एफ) के बाद निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात:

"(जी) 1 नवंबर 2017 से या उसके बाद से, अन्य सभी बातें समान रहते हुए, विनिर्दिष्ट निजी वेतन के साथ आवास किराया भत्ता निम्नलिखित दर पर दिया जाएगा और यह पूरी सेवा अवधि के दौरान समान ही रहेगा:-

तालिका		
वेतनवृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटकों पर 01.11.2017 को लागू महंगाई भत्ता (रु)	जहां बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया जाता है वहां देय कुल निश्चित निजी वेतन (रु)
(1)	(2)	(3)
1. 1990	53	2043
2. 2220	59	2279
3. 2500	66	2566
4. 2730	73	2803
5. 2970	79	3049
6. 3220	86	3306

नोट :

- (i) टेबल के कॉलम (3) के उपबंध (बी), (सी), (डी) या (ई) के अंतर्गत वर्णितानुसार विनिर्दिष्ट निजी भत्ता या विनिर्दिष्ट निजी वेतन उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक की ओर से आवास उपलब्ध कराया गया है।
- (ii) जो अधिकारी आवास किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे उनके लिए विनिर्दिष्ट निजी भत्ता या विनिर्दिष्ट निजी वेतन, सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उठाए जा रहे आवास किराया भत्ता जो उसे विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5), (6) व (7) में निर्दिष्ट समुचित वेतनमान के अंतिम वेतनवृद्धि के समय प्राप्त हो रहे होंगे और उपरोक्त वर्णित टेबल के कॉलम (1) व (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुल राशि होगी।
- (iii) केवल वे अधिकारी जो 1 नवंबर 1993 को या उससे पहले से बैंक में कार्यरत हैं, वे अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के एक वर्ष बाद निश्चित निजी वेतन के लिए पात्र होंगे।
- (iv) 1 नवंबर 1999 से, निश्चित निजी वेतन जारी होने के कारण उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (सी) के अनुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन निर्गमित करने की समय अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा:
बशर्ते कि जहां व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई भी किस्त, जो पहले के प्रावधानों के कारण एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी गई हो और जो 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी करने के लिए निर्धारित है, वह इस तिथि से अधिकारी को निर्गमित की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 1 नवंबर, 2000 को जारी की जाएगी।
- (v) निश्चित निजी भत्ते या निश्चित निजी वेतन के वेतन वृद्धि घटकों का उपयोज सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु किया जाएगा।

(vi) उपर्युक्त उपबंध (ए) के अनुसार यदि किसी अधिकारी ने अग्रिम वेतनवृद्धि हासिल कर ली है तो उसे उपबंध (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) में वर्णितानुसार निर्धारित निजी भत्ता/ निर्धारित निजी वेतन की प्रमात्रा का भुगतान उसे स्केल में सर्वोच्च पर पहुंचने के एक साल बाद ही प्रदान किया जाएगा।

5. उक्त विनियम के विनियम 20 में, उप-विनियम (1) में, खंड (सी) में, "अध्यक्ष एवं" शब्दों को विलुप्त किया जाएगा।

6. कथित विनियमों के विनियम 21 में, -

(i) उप-विनियम (6) में, स्पष्टीकरण में, खंड (बी) में, कोष्ठक, शब्द और अक्षर "(एफ) और (जी)" के लिए, कोष्ठक, शब्द और अक्षर "(एफ), (जी) और (एच)" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-विनियम (6) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात:-

"(7) नवंबर 2017 के पहले दिन से या उसके बाद, महंगाई भत्ता 6352 अंक में प्रत्येक चार अंक की कटौती या बढ़ोतरी पर ऑल इंडिया एवरेज वर्किंग क्लास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सामान्य) बेस 1960=100 के तिमाही औसत का, वेतनमान के 0.07% की दर से देय होगा।

7. कथित विनियमों के विनियम 22 के उप-विनियम (1) को निम्नलिखित उप-विनियम से विस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(1) नवंबर 2017 की पहली तिथि से और उसके बाद,

(ए) जहां किसी भी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उससे जिस वेतनमान में हो उसके पहले चरण में मूल वेतन का 0.50% के बराबर की राशि अथवा आवास के लिए मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूला जाएगा;

(बी) जहां कहीं भी किसी अधिकारी को यदि बैंक की ओर से रहने की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है वो अधिकारी निम्नलिखित टेबल में विरिन्दिष्टानुसार आवास किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, अर्थात:

तालिका

कार्यस्थल	आवास किराया भत्ता
(1)	(2)
1. प्रमुख "ए" वर्ग के शहर और समूह ए के एरिया केंद्र	वेतन का 9.0%
2. एरिया 1 के अन्य शहर एवं समूह बी के प्रोजेक्ट एरिया केंद्र व गोवा राज्य	वेतन का 8.0%
3. अन्य स्थान	वेतन का 7.0%:

यह भी प्रावधान किया जाता है कि यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है तो, उसको देय आवास किराया भत्ता उसके घर के वास्तविक किराए के बराबर होगा जो कि जिस वेतनमान में वो है उसके प्रथम चरण के वेतन के 0.50% के साथ टेबल के कॉलम (2) में प्रदत्त के अनुसार आवास किराया भत्ता का 150% देय होगा।

नोट-मालिकाना आवास के लिए लागत से लिंकड आवास किराया भत्ते के लिए अधिकारी का दावा भी अब तक जैसा होता रहा है उसी अनुसार आवास किराया भत्ते का 150% तक सीमित रहेगा।“

8. कथित विनियमन के 23 विनियम में-

(क) खंड (i) से (v) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(i) नवंबर 2017 की पहली तिथि से और उसके बाद, यदि कोई अधिकारी निम्नवर्णित तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित स्थान पर कार्यरत है, तो उस स्थान के लिए उसे कॉलम (2) में उल्लिखित दर पर शहर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा। .

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
1. एरिया I व उससे ऊपर व गोवा राज्य	रु. 1400/- प्रति माह
2. पांच लाख और उससे अधिक की आबादी वाले स्थान और राज्य की राजधानियाँ और चंडीगढ़, पुदुचेरी और पोर्ट ब्लेयर	रु. 1150/- प्रति माह;

(ii) नवंबर 2017 की पहली तिथि से और उसके बाद से विशेष क्षेत्र भत्तों की दरें इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगी;

(iii) नवंबर 2017 की पहली तिथि से और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी समूह ए या समूह बी में आने वाले परियोजना क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र में कार्यरत है, तो वह समूह ए या समूह बी के रूप में क्षेत्र का वर्गीकरण के आधार पर क्रमशः 600/- रुपये प्रति माह या 525/- रुपये प्रति माह की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होगा।;

(iv) नवंबर 2020 की पहली तिथि से और उसके बाद से यदि कोई अधिकारी शैक्षिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसको एक या अधिक बच्चे पहले वाले स्थान में स्थित स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वह अपने सभी बच्चों के लिए दूसरे स्थान पर रिपोर्ट करने की तिथि से शैक्षिक वर्ष की समाप्ति तक प्रतिमाह रु 1650 के मध्य शैक्षिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते के लिए पात्र होगा, बशर्ते यदि पहले स्थान पर पढ़ने वाले उसके सभी बच्चे यदि पढाई छोड़ देते हैं तो ऐसा भत्ता देय नहीं होगा।

(ii) नवंबर 2020 की पहली तिथि से और उसके बाद से यदि कोई अधिकारी बैंक से बाहर सेवा हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह उस पद से जुड़े वेतन लाभ को प्राप्त कर सकता है जिसके लिए उसे प्रतिनियुक्त किया गया है या अपनी वेतन के अतिरिक्त वह वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि यह भत्ता प्रतिमाह रु 6000 से अधिक न हो। इसके अलावा वह ऐसे अन्य भत्ते भी आहरित कर सकता है जो उसको उस स्थान पर बैंक की सेवा में नियुक्त करने पर मिलते हैं।

उसे अपने वेतन के 4 प्रतिशत के समतुल्य प्रतिनियुक्त भत्ता प्राप्त होगा जो रु. 3000 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा बशर्ते उसे ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया गया है जो उसी स्थान पर है जहाँ उसे प्रतिनियुक्ति से तुरंत पहले नियुक्त किया गया था।

बशर्ते कि यदि किसी अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह अपने वेतन के 4 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्त भत्ते के लिए पात्र होगा जो रु 3000 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(ख) खंड (8) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(viii) नवंबर 2017 की पहली तिथि से और उसके बाद से, यदि एक दिन के दौरान काम के घंटों को न्यूनतम दो घंटे के अंतराल के साथ विभाजित किया जाता है, तो एक अधिकारी 300 रुपये प्रति माह की दर से स्प्लिट ड्यूटी भत्ते के लिए पात्र होगा।";

(ग) खंड (10) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(10) नवंबर 2017 की पहली तिथि से और उसके बाद से, अधिकारी निम्न वर्णित तालिका में निर्दिष्टानुसार पहाड़ व ईंधन भत्ते के लिए पात्र होंगे, अर्थात्:

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
1. 1000 मीटर और उससे अधिक लेकिन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मदिकेरी नगर	वेतन का 2% अधिकतम रु. 1125/- प्रति माह
2. 1500 मीटर और उससे अधिक लेकिन 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 2.5%, अधिकतम रु.1500/- प्रति माह
3. 3000 मीटर तथा उससे अधिक ऊँचाई वाले स्थान	वेतन का 5%, अधिकतम रु. 3000/- प्रति माह";

(घ). खंड (10) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

"(xi) नवंबर 2017 की पहली तिथि से और उसके बाद से, अधिकारी महंगाई भत्ते के साथ प्रति माह 600/- रुपये के शिक्षण भत्ते के लिए पात्र होंगे ;

(xii) नवंबर 2017 की पहली तिथि से और उसके बाद से, वैसे अधिकारी प्रति माह 700/- रुपये के निश्चित भत्ते के लिए पात्र होंगे, जो शहरी प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में तैनात हैं और यह निश्चित भत्ता महंगाई भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात्, नई पेंशन योजना, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी सहित पेंशन के भुगतान के लिए नहीं गिना जाएगा।;

(xiii) वित्तीय वर्ष 2020-21 से, प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन सभी अधिकारियों को वार्षिक रूप से देय सामान्य वेतन के अलावा परिचालन लाभ या निबल लाभ के आधार पर देय होगा, और नीचे दी गई तालिका में

उल्लिखित प्रदर्शन लिंकड इंडेक्स मैट्रिक्स देय राशि तय करेगा (वेतन के दिनों की संख्या में = मूल + महंगाई भत्ता) जो कि बैंक के वार्षिक प्रदर्शन पर निर्भर करता है।

तालिका

क्र. सं.	परिचालनगत लाभ में वर्ष- दर- वर्ष की वृद्धि	दिनों की संख्या जिनके लिए वेतन (मूल+महंगाई भत्ता) का भुगतान किया जाएगा
(1)	(2)	(3)
1.	< 5%	शून्य
2.	5% to 10%	5 दिन
3.	> 10% to 15%	10 दिन *
4.	> 15%	15 दिन *
*तीसरी और चौथी स्लैब केवल तभी देय होती है जब बैंक को निवल लाभ होता है। यदि किसी बैंक के परिचालन लाभ में 5 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन कोई निवल लाभ नहीं है, तो 5 दिनों का न्यूनतम दूसरा स्लैब देय होगा।		

9. उक्त विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1) 1 नवंबर, 2017 से अधिकारी स्वयं तथा परिवार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रमाण पत्र में दावा की गई राशि के लिए लेखा विवरण के साथ समर्थित व्यय किए जाने का प्रमाण पत्र हो, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं	ग्रेड	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन ग्रेड	रु.10300/- प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि जो भी कम हो
2.	वरिष्ठ प्रबंधन and Top कार्यपालक ग्रेड	रु.12300/- प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि जो भी कम हो

स्पष्टीकरण.- इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए,-

- "किसी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते किसी भी समय उक्त प्रदत्त अधिकतम राशि से तीन गुना अधिक न हो; अथवा
- वर्ष 2017 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी, अर्थात् नवंबर, 2017 और दिसंबर, 2017 हेतु।"

10. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(2) " उप-विनियम (1) में किसी भी बात के बावजूद, बैंक किसी अधिकारी को 1 नवंबर, 2017 से 0.50 प्रतिशत के बराबर, जिस वेतनमान में उसे रखा गया है, उसके पहले चरण में मूल वेतन या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो उतनी राशि का भुगतान करने पर आवासीय आवास प्रदान करेगा, :

बशर्ते कि जहाँ अधिकारी को ऐसे निवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, तो बैंक उस वेतनमान के पहले चरण में मूल वेतन के 0.10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि उससे वसूल करेगा :

बशर्ते कि, जहाँ ऐसा आवासीय आवास बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है, बिजली, पानी, गैस और सफाई का शुल्क अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।"

11. उक्त विनियमों के विनियम 32 में, उप-विनियम (2) में, प्रावधान के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण होगा, अर्थात्: -
स्पष्टीकरण -

इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि -

(क) वर्ष 2017 या उसके बाद के वर्षों में नहीं लिया गया आकस्मिक अवकाश अगले पांच वर्षों में समाप्त हो जाएगा; और

(ख) 1 नवंबर, 2020 को और उसके बाद से, अधिकारी द्वारा चिकित्सा आधार पर अप्राप्त आकस्मिक छुट्टी की अनुमति दी जाएगी और चार दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसे अप्राप्त आकस्मिक अवकाश की अवधि के लिए किसी चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. उक्त विनियमों के विनियम 33 में -

(क) उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(4) 1 जून, 2015 को और उसके बाद से, विशेषाधिकार अवकाश दो सौ सत्तर दिनों से अधिक नहीं जमा किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जहाँ अवकाश के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो: बशर्ते कि विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम 240 दिनों तक सीमित होगा :

बशर्ते कि कैलेंडर वर्ष 2020 से, एक अधिकारी अपनी पसंद के किसी भी त्योहार के समय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए पांच दिनों की दर से विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण के लिए पात्र होगा और एक अधिकारी जो पहले ही पचपन वर्ष पूरा कर चुका है 1 जनवरी, 2020 और उससे अधिक आयु के व्यक्ति एक बार के उपाय के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए सात दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश नकदीकरण के पात्र होंगे।

(ख) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(5) विशेषाधिकार अवकाश का लाभ उठाने के इच्छुक अधिकारी को, अवकाश किराया रियायत के उद्देश्य को छोड़कर, ऐसी छुट्टी का लाभ उठाने के अपने इरादे के बारे में आम तौर पर कम से कम दस दिन का नोटिस देना होगा।

(6) जब अधिकारी के बीमार अवकाश खाते में कोई क्रेडिट नहीं है, तो बीमारी के आधार पर ली गई विशेषाधिकार छुट्टी को विशेषाधिकार अवकाश प्राप्त करने के अवसर के रूप में नहीं गिना जाएगा।”

13. उक्त विनियमों के विनियम 34 में, उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित विनियम शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

“(5) महिला अधिकारी अपने आठ वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर बीमारी की छुट्टी का लाभ उठा सकती हैं।”

14. उक्त विनियमों के विनियम 35 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“35. अतिरिक्त रुग्ण अवकाश - (1) 1 जनवरी 1989 से, जहाँ एक अधिकारी ने चौबीस वर्ष से अधिक की सेवा का पूरी की है, वह अधिकतम तीन महीने की अतिरिक्त रुग्ण अवकाश के अधीन, प्रत्येक महीने के लिए एक महीने की दर से अतिरिक्त रुग्ण अवकाश के लिए पात्र होगा।

(2) 1 जनवरी, 2017 से, जहाँ एक अधिकारी ने तीस साल की सेवा कर ली है, वह तीस साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने की दर से अधिकतम तीन महीने की अतिरिक्त रुग्ण अवकाश के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि अधिकारी की पूरी सेवा में बीमार छुट्टियों की कुल संख्या सात सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि 29 जून, 1999 को या उसके बाद ली गई अतिरिक्त बीमार छुट्टियों के मामले में, विनियम 34 के उप-विनियम (2) के अनुसार अतिरिक्त छुट्टी के परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।

15. उक्त विनियम के विनियम 36 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“36. मातृत्व अवकाश - (1) मातृत्व अवकाश के मामले में -

(क) एक महिला कर्मचारी किसी एक अवसर पर छह महीने से अधिक की अवधि के लिए और अपनी सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने के लिए मूल वेतन पर मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी:

बशर्ते कि जुड़वा बच्चों के जन्म के मामले में मातृत्व अवकाश की अवधि आठ महीने होगी।

बशर्ते कि मातृत्व अवकाश का लाभ आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मिलाकर लिया जा सकता है;

(ख) गर्भपात या गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के मामले में, एक महिला कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र या एक सक्षम चिकित्सा व्यवसायी, यानी एक योग्य स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर और चिकित्सा से जुड़े विशेष या

असाधारण मामलों में छह सप्ताह तक मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सकती है। गर्भपात या गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन या गर्भपात से जुड़ी जटिलताओं के लिए, योग्य स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा सलाह दिए जाने पर छह सप्ताह से अधिक मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने कुल सीमा के भीतर किसी एक अवसर पर केवल छह महीने तक ही होगा।

(ग) बारह महीने की कुल अवधि के भीतर, हिस्टेरेक्टॉमी के मामले में अधिकतम साठ दिनों तक की छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है।

नोट: उन कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने बारह महीने की मातृत्व छुट्टी ले ली है और समाप्त कर ली है, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन, पंद्रह दिनों की छुट्टी स्वीकृत की जाएगी;

(घ) एक निःसंतान महिला कर्मचारी एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए सेवा के दौरान एक बार अधिकतम नौ महीने की अवधि के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन छुट्टी ले सकती है, अर्थात्: -

- i. केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए ली गई छुट्टी;
- ii. बच्चे को गोद लेना उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होगा, कर्मचारी को ऐसी छुट्टी की मंजूरी के लिए बैंक को गोद लेने का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा;
- iii. स्थायी अंशकालिक कर्मचारी भी एक बच्चे को गोद लेने हेतु छुट्टी के लिए पात्र हैं;
- iv. यह छुट्टी उन मामलों में जैविक मां को भी उपलब्ध होगी जहां बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ है;
- v. सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने की समग्र पात्रता के भीतर छुट्टी का लाभ उठाया जाएगा;

(ङ) बारह महीने की कुल अवधि के भीतर, निम्नलिखित स्त्रीरोग संबंधी बीमारियों या उपचार के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में अधिकतम तीस दिनों तक छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है, अर्थात्: -

- i. एयूबी (अबनार्मल यूट्रिन ब्लीडिंग)
- ii. ओवेरियन ट्यूमर
- iii. ट्यूबेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी रिवर्सल
- iv. पोस्ट पार्टम ड्रिपेशन (पीपीडी)
- v. पोस्ट पार्टम हेमोरेज (पीपीएच)
- vi. एक्यूट पैल्विक इन्फ्लेमेट्री रोग (एक्यूट पीआईडी)
- vii. डाइफ्यूज़न यूट्रिन ब्लीडिंग (डीयूबी)

(2) "पितृत्व अवकाश के मामले में, 1 जून, 2015 से दो जीवित बच्चों वाले पुरुष कर्मचारी अपनी पत्नी के कारावास के दौरान पंद्रह दिनों के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगे और इस अवकाश को आकस्मिक अवकाश के अलावा किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है :

बशर्ते कि छुट्टी बच्चे के जन्म की तारीख से पंद्रह दिन पहले या छह महीने तक ली जा सकती है।

बशर्ते कि ऊपर बताए अनुसार पितृत्व अवकाश दो जीवित बच्चों वाले पुरुष कर्मचारी को एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए दिया जाएगा।"

16. उक्त विनियमों के विनियम 37 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

37. असाधारण छुट्टी - (1) एक अधिकारी सेवा की पूरी अवधि के दौरान चौबीस महीने से अधिक नहीं के लिए वेतन हानि पर असाधारण छुट्टी के लिए पात्र होगा।

(2) एक अधिकारी किसी एक अवसर पर तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए असाधारण छुट्टी का लाभ उठा सकता है और अत्यधिक चिकित्सा परिस्थितियों में, वह किसी एक अवसर पर चार महीने तक की असाधारण छुट्टी का लाभ उठा सकता है।

ध्यान दें: चिकित्सा आधार पर असाधारण छुट्टी लेने पर कर्मचारी को कोई वरिष्ठता की हानि नहीं होगी।

17. उक्त विनियमों के विनियम 37ए के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

37क - विशेष आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश -

(1) 1 नवंबर 2020 से, एक अधिकारी कर्मचारी उन अवसरों पर विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा जब वह शाखा जहाँ अधिकारी काम कर रहा है या वह स्थान जहाँ वह निवास कर रहा है, कर्फ्यू, दंगों, निषेधात्मक आदेशों, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है।

(2) 1 नवंबर, 2020 से, शारीरिक या हड्डी से विकलांग अधिकारी चार दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा।

(3) किसी अधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश और समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय की गई कोई विशेष छुट्टी भी दी जा सकती है।

18. उक्त विनियमों के विनियम 41 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ए) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(क) विराम भत्ता : नवंबर 2020 के 1 दिन से, तालिका के कॉलम (1) में निर्धारित ग्रेड या स्केल में एक अधिकारी कॉलम में निर्धारित संबंधित दरों पर प्रति दिन हॉल्टिंग भत्ते का पात्र होगा अर्थात् :-

तालिका

अधिकारियों के वेतन ग्रेड या वेतनमान	मेट्रो रु.	मुख्य 'ए' श्रेणी शहर	एरिया - I रु.	अन्य स्थान रु.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. स्केल VI व ऊपर के अधिकारी	2700	1950	1650	1425
2. स्केल IV व V अधिकारी	2250	1950	1650	1425
3. स्केल I, II व III अधिकारी	1950	1650	1/125	1200:

बशर्ते कि जहाँ अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम लेकिन चार घंटे से अधिक हो, तो उपरोक्त दरों की आधी दर पर विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण - ठहराव भत्ते की गणना के प्रयोजन के लिए "प्रति दिन" का अर्थ हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय और आगमन के वास्तविक समय तक, अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से गणना की गई चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसके बाद के हिस्से से होगा, और जहाँ अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, "प्रति दिन" का अर्थ आठ घंटे से कम की अवधि नहीं होगी।'

19. उक्त विनियम के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) नवंबर, 2020 के पहले दिन से, स्थानांतरण पर एक अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि से जुड़े खर्चों के लिए एकमुश्त राशि आहरित करने के लिए पात्र होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है। अर्थात्:

तालिका

ग्रेड या स्केल	राशि
(1)	(2)
उच्च कार्यकारी और वरिष्ठ प्रबंधन (स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारी)	रु. 30,000/-
2. मध्य प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन (स्केल III तक के अधिकारी)	रु. 25,000/-

20. उक्त विनियमों के विनियम 45 में, उप-विनियम (4) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात्: -

"बशर्ते कि परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) के तहत कवर किए गए अधिकारियों के संबंध में, बैंक 11 नवंबर, 2020 से वेतन और महंगाई भत्ते का चौदह प्रतिशत योगदान देगा:

बशर्ते कि नई पेंशन योजना के सेवा प्रदाता या फंड मैनेजर का सेवा शुल्क वित्तीय वर्ष 2020-21 से बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

21. उक्त विनियमों की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"अनुसूची

[विनियम 23 का खंड (ii) देखें]

1 नवंबर, 2017 से, एक अधिकारी विशेष क्षेत्रों के भत्तों के लिए तब तक पात्र होगा जब तक कि उन्हें पूरी तरह या आंशिक रूप से वापस नहीं लिया जाता या संशोधित नहीं किया जाता, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्: -

तालिका
विशेष क्षेत्र भत्ता

क्र. सं.	क्षेत्र (केंद्र शासित प्रदेश राज्य)	भत्ते (रुपये)	
		रु.36,000/- के नीचे वेतन	रु.36,001/-के ऊपर वेतन
		रु .	रु .
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मिजोरम (अ) चिम्पटुईपुई जिला और लुंगलेई जिले के लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से अधिक दूर के क्षेत्र।	4000	5200
	(ब) लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण लुंगलेई जिला।	3200	4200
	(स) संपूर्ण आइजोल जिला	2400	3000
2.	नागालैंड	3200	4200
3.	अंडमान और निकोबार (अ) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार और नारकोंडम द्वीप समूह	4000	5200
	(ब) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	3200	4200
4.	सिक्किम	4000	5200
5.	लक्षद्वीप	4000	5200
6.	असम	640	800
7.	मेघालय	640	800
8.	त्रिपुरा (अ) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	3200	4200
	(ब) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर पूरे त्रिपुरा में	2400	3000
9.	मणिपुर	2400	3000
10.	अरुणाचल प्रदेश (अ) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	4000	5200
	(ब) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर पूरे अरुणाचल प्रदेश में।	3200	4200
11.	जम्मू और कश्मीर (1) कठुआ जिला: नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मछोड़ी	4000	5200

	(2) उधमपुर जिला: (अ) डुडु बसंतगढ़, लैंडर भमाग इलाका, भाग 2 (बी) में शामिल लोगों के अलावा।	4000	5200
	(ब) तहसील मोहर में कबन की ओर से गोयल तक के क्षेत्र और केसी की ओर से अरनास तक के क्षेत्र।	3200	4200
	(3) डोडा जिला: किश्तवाड़ तहसील में पैडर और नियाबत नौगाम के इलाके	4000	5200
	(4) लेह जिला: जिले के सभी स्थानों पर	4000	5200
	(5) बारमुल्ला जिला: (अ) संपूर्ण गुरेज़-निराबत, तंगदार उप-मंडल और केरन इलाके	4000	5200
	(ब) मैचिल	3200	4200
	(6) पुंछ और राजौरी जिले: पुंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र, पुंछ और राजौरी और सुंदरबनी शहरों और दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर	2400	3000
	(7) वे क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (6) में शामिल नहीं हैं, लेकिन जो 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा से या उन स्थानों से जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर सीमा भत्ते के लिए योग्य घोषित किया जा सकता है।	2400	3000
12.	हिमाचल प्रदेश (1) चंबा जिला (अ) पांगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायतें: बड़गांव, बजोल, देवल कुगती, नयागाम और तुंदाह, गांव: ग्राम पंचायत जगत के घाटू, ग्राम पंचायत चौहाटा के कनारसी	4000	5200
	(ब) भरमौर तहसील, ऊपर (ए) में शामिल पंचायतों और गांवों को छोड़कर।	3200	4200
	(स) भटियात तहसील में झंडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी शहर (बनीखेत सहित)	2400	3000
	(2) किन्नौर जिला: (अ) आसरंग, चिटकुल और हांगो कूनो/चारंग पंचायतें, 15/20 क्षेत्र जिसमें ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर, पूह उपमंडल के छोटा खंबा, नाथपा और रूपी की ग्राम पंचायतें शामिल हैं।	4000	5200
	(ब) उपरोक्त (ए) में शामिल क्षेत्रों के अलावा पूरा जिला।	3200	4200
	(3) कुल्लू जिला: (अ) निरमंड तहसील का 15/20 क्षेत्र, जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायतें शामिल हैं	4000	5200

	(ब) बाहरी सराज (निरमंड तहसील में जकात-खाना और बरो के गांवों को छोड़कर) और संपूर्ण जिला बाहरी सराज क्षेत्र और पंद्राबीस के परगना को छोड़कर, लेकिन तहसील निरमंड के जगत-खाना और बरो गांवों सहित)।	2400	3000
	(4) लाहौल और स्पीति जिला: लाहौल और स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र	4000	5200
	(5) शिमला जिला: (अ) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा और चाडी-ब्रांडा की पंचायतें शामिल हैं।	4000	5200
	(ब) डोरा-कावर तहसील, रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील और मुनीश, परगना सराहन की गोरी चैबीस।	3200	4200
	(स) चौपाल तहसील और परगना सराहन के घोरी, पंजगांव, पाटसनौ, नौबीस और तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत, परगना बाराबीस, रामपुर तहसील के परगना रामपुर के कस्बा रामपुर और घोरी नोग, शिमला शहर और उसके उपनगर (ढल्ली, जतोग, कसुम्पटी, मशोबरा, तारादेवी और टूटू)।	2400	3000
	(6) कांगड़ा जिला: (अ) बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के क्षेत्र	3200	4200
	(ब) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर और नगर निगम सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय, लेकिन धर्मशाला शहर में शामिल हैं- महिला आईटीआई, दारी, मैकेनिकल कार्यशाला, रामनगर, बाल कल्याण और शहर और देश नियोजन कार्यालय, सकोह, निचले सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दूध आपूर्ति योजना, डुगियार, एचआरटीसी कार्यशाला, साधेर, आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दाड़ी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्ट्री, दाड़ी, आई.पी.एच. उप-मंडल, दान, निपटान कार्यालय, शामनगर, हिंवा परियोजना, शामनगर। कांगड़ा जिले का पालमपुर शहर, जिसमें पालमपुर में एचपीकेवीवी परिसर और इसके नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय शामिल हैं, लेकिन पालमपुर शहर में शामिल हैं - एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय परिसर, मवेशी विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बनुरी, रेशम उत्पादन कार्यालय/इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला/एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुंडला, विद्युत उप-मंडल, लोहना, डी.पी.ओ. निगम, बुंडला, इलेक्ट्रिकल एचईएसईई डिवीजन, घुग्गर	2400	3000
	(7) मंडी जिला: जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, थुनाग तहसील की पंचायतें- बगड़ा, छतरी, छोटधार, गरागुशैन, गटू, गरयास, जंजैहली, जरयार, जोहार,		

	कल्हणी, कलवन, खोलानाल, लोथ, सिलीबागी, सोमाचन, थाचधार, ताची, थाना, की पंचायतें धर्मपुर ब्लॉक- बिंगा, कमलाह, सकलाना, तनयार और ताराखोला, करसोग की पंचायतें तहसील - बालीधार, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुडी, मंज, पेखी, सेंज, सराहन और तेबन, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें - बोही, बटवाडा, धन्यारा, पौडा-कोठी, सेरी और शोजा।	2400	3000
	(8) सिरमौर जिला: बानी, बाखली (पच्छाद तहसील), भरोग भनेरी (पांवटा तहसील), बिड़ला (नाहन तहसील), डिब्बर (पच्छाद तहसील) और थाना कसोगा (नाहन तहसील) और थांसगिरि क्षेत्र की पंचायतें	2400	3000
	(9) सोलन जिला: मंगल पंचायत.	2400	3000
	(10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र उपरोक्त (1) से (9) में शामिल नहीं हैं।	640	800
13.	उत्तर प्रदेश: चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तर काशी जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	4000	5200
14.	उत्तराखंड: चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	4000	5200
15.	पश्चिम बंगाल दक्षिण 24 परगना जिला सुंदरबन क्षेत्र (डैम्पियर हॉज की रेखा के दक्षिण), अर्थात्, भगतुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), झिंगा खली, सजनाखली, गोसाबा, अमलमथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नलगराहा, रैदिघी, भांची, पत्थर प्रतिमा, भागवतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सीकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसियोनी, कालीनगर, हराओ, हिंगलगंज, बसंती, कुएमारी, कुलटोला, घुसीघटा (कुल्टी)	1000	1000.”.

दिलीप कुमार बारिक, महा प्रबन्धक – एचआर

[विज्ञापन-III/4/असा./729/2024-25]

नोट: इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किया गया: -

क्र.सं.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	31/SUP/97	12.01.1988	13.02.1988
2.	31/SUP/861	07.05.1988	28.05.1988

3.	31/SUP/2139	29.07.1988	22.10.1988
4.	PAD/177/3/88	09.12.1989	30.12.1989
5.	PAD/177/1/89	09.12.1989	30.12.1989
6.	PAD/177	05.03.1994	09.04.1994
7.	PAD/177	21.07.1995	28.10.1995
8.	PAD/177	17.08.1996	09.11.1996
9.	PAD/177	19.11.1996	07.12.1996
10.	PAD/177	12.05.1999	12.06.1999
11.	PAD/SUP/177	09.09.1999	09.10.1999 and 16.10.1999
12.	PAD/SUP/177	22.05.2000	17.06.2000
13.	PAD/SUP/177	28.08.2001	08.09.2001
14.	PAD/SUP/177	29.11.2002	21.12.2002
15.	PAD/SUP/177/49	10.05.2006	08.06.2006
16.	PAD/SUP/177	25.03.2008	05.04.2008
17.	HRMD/SUP/177/001	28.03.2019	08.02.2021
18.	HRMD/SUP/177/002	28.03.2019	08.02.2021
19.	HRMD/SUP/177/01/2021-22	08.02.2022	16.02.2022

विवरणात्मक ज्ञापन

ये नियम जिन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, वे इस संबंध में संबंधित बैंकों और शीर्ष स्तर के अधिकारियों द्वारा दिए गए विशिष्ट आदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से बैंकों के संघ और भारतीय बैंक संघ के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोट्स के सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार हैं। इसलिए, ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

INDIAN OVERSEAS BANK

NOTIFICATION

Chennai, the 2nd December, 2024

F. No. HRMD/SUP/177/01/2024-25.—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Indian Overseas Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services letter No. 4/2/2015-IR, dated the 18th December, 2020, on and from the 1st November, 2017 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Overseas Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

- (1) These regulations may be called the Indian Overseas Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Overseas Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,-

(i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(f) "family", for the purpose of medical facilities and for the purpose of leave fare concession, means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children) wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with forty per cent or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters and parents wholly dependent on the officer.

Explanation 1.— For the purposes of this clause,-

(i) the expression “wholly dependent family member” shall mean such member of the family having an income not exceeding ₹12,000/- per month and if the income of one of the parents exceeds ₹12,000/- per month or the aggregate income of both the parents exceeds ₹12,000/- per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer; and

(ii) a married female officer may include her natural parents or parents-in-law under the definition of family, but not both, provided such parents or parents-in-law are wholly dependent on her.

Explanation 2.- For the purpose of medical expenses reimbursement scheme, for all officers, that is, male or female, any two of the dependent parents or parents-in-law shall be covered and the officer shall have the choice to substitute either of the dependents or both.

Explanation 3.- Physically challenged children of an officer shall be considered as dependents irrespective of age or marital status, subject to income criteria;’;

(ii) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

(i) “Managing Director” means the Managing Director and the Chief Executive Officer of the Bank;”.

3. In regulation 4 of the said regulations,-

(a) in sub-regulation (6), the *Explanation* shall be omitted;

(b) for sub-regulation (7), the following sub regulations shall be substituted, namely:-

" (7) On and from the 1st day of November, 2017, the scales of pay specified against each grade shall be as under:-

(a) Top Executive Grade

Scale VII = ₹116120 – 3220/4 – 129000

Scale VI = ₹104240 - 2970/4 – 116120

(b) Senior Management Grade

Scale V = ₹89890 – 2500/2 – 94890 – 2730/2 - 100350

Scale IV = ₹76010 – 2220/4 – 84890– 2500/2 – 89890

(c) Middle Management Grade

Scale III = ₹63840 – 1990/5 – 73790 - 2220/2 - 78230

Scale II = ₹48170 - 1740/1 - 49910 - 1990/10 - 69810

(d) Junior Management Grade

Scale I = 36,000 – 1490/7- 46430– 1740/2– 49910– 1990/7-63840

Explanation.- Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on the 31st October, 2017 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2017 on stage-to-stage basis, that is, on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

- (8) Nothing in sub-regulations (1) to (7) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades."
- (9) (a) on and from the 1st day of November, 2012, officers shall be paid special allowances as under:-

Scale I-III - 7.75% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon
 Scale IV-V - 10% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon
 Scale VI-VII - 11% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

- (b) On and from the 1st day of November, 2017, officers shall be paid special allowances as under:-

Scale I-III - 16.40% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon
 Scale IV-V - 19% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon
 Scale VI-VII - 20% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Explanation.- The special allowance referred to in clauses (a) and (b) with applicable dearness allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including New Pension Scheme, provident fund and gratuity."

4. In regulation 5 of the said regulations, -

- (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to the provisions of sub-regulation (7) of regulation 4, on and from the 1st November, 2017, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (7) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which such increments fall due;
- (b) one year after reaching the maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increments in the next higher scale, as specified in clause (c), subject to their crossing the efficiency bar;
- (c) officers in junior management grade Scale I, who have moved to scale of pay for middle management grade Scale II in terms of clause (b), after reaching maximum of the higher scale, shall be eligible for five stagnation increments for every two completed years of service of which the first two shall be Rs. 1990/- each and the next three of Rs 2220/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment two years after release of the fourth stagnation increment, or on the 1st November, 2017, whichever is later;

- (d) officers in middle management grade Scale II, who have moved to scale of pay for middle management grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher scale, shall be eligible for five stagnation increments of Rs 2220/- each for every two completed years of service:

Provided that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment two years after release of fourth stagnation increment or on the 1st November, 2017, whichever is later;

- (e) officers in substantive middle management grade Scale III, that is, those who are recruited in or promoted to middle management grade Scale III, shall be eligible for six stagnation increments out of which first four stagnation increments of Rs 2220/- each shall be granted for every two years of completed service after reaching the maximum and the next two stagnation

increments of Rs 2500/- each shall be granted for every two years of completed service after receiving the fourth stagnation increment:

Provided that the sixth stagnation increment shall be released two years after release of fifth stagnation increment or on the 1st November, 2017, whichever is later;

- (ii) officers in senior manager grade Scale IV shall be eligible for two stagnation increments after reaching the maximum of scale, for every two completed years of service, of which first stagnation increment shall be of Rs 2500/- and the second stagnation increment shall be of Rs 2730/-:

Provided that the officer shall be eligible for the second stagnation increment two years after release of first stagnation increment, or on the 1st November, 2017, whichever is later;

- (iii) the stagnation increments received by the officers from Scale I to Scale IV during their service in the Bank, as on the 1st November, 2017 as per periodicity hereinbefore shall be readjusted from three years periodicity to two years periodicity from the date of reaching their maximum and the officer shall be notionally eligible for stagnation increments with effect from the 1st November, 2017 as per the revised periodicity, which will qualify for superannuation benefits:

Provided that the monetary benefit on account of such revised and readjusted periodicity of stagnation increments shall be payable from the 1st November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later;

- (iv) officer in senior management grade Scale V shall be eligible for one stagnation increment of Rs 2970/- two years after reaching the maximum scale of pay, or on the 1st November, 2020, whichever is later:

Provided that such increments shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation.- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.";

- (b) in sub-regulation (2), in the *Explanation*, after the proviso to clause (g) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely: -

- "(h) on and from the 1st November, 2017, other things being equal, the quantum of professional qualification pay shall stand revised as specified in the Table below: -

TABLE

(1)	(2)
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers Part I	(i) Rs. 1020 per month one year after reaching maximum of the scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(a) Rs. 1020 per month, one year after reaching maximum of the scale. (b) Rs. 2550 per month, two years after reaching maximum of the scale:

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of professional qualification pay and the release of subsequent installments of professional

qualification pay shall be with reference to the date of release of first installment of such professional qualification pay.";

(c) in sub-regulation (3),-

- (i) in clause (f); after the Table, Notes (i) to (vi) shall be omitted;
- (ii) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: -

"(g) on and from the 1st November, 2017, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Increment component (Rs.)	Dearness Allowance as on The 1 st November, 2017 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1. 1990	53	2043
2. 2220	59	2279
3. 2500	66	2566
4. 2730	73	2803
5. 2970	79	3049
6. 3220	86	3306

Note:

- (i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Tables in clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of this sub-regulation shall be payable to those officers who are provided with Bank's accommodation.
- (ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the aforesaid Table and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4), (5), (6) and (7) of regulation 4 is earned.
- (iii) Only officers who are in the service of the Bank on or before 1st November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay, they are placed.
- (iv) On and from the 1st November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in the Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of professional qualification pay, which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and the second installment of professional qualification pay, if any, shall be released on the 1st November, 2000.

- (v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
- (vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in (b), (c), (d), (e), and (f) above, one year after reaching the maximum of the scale."

5. In regulation 20 of the said regulations, in sub-regulation (1), in clause (c), the words "Chairman &" shall be omitted.

6. In regulation 21 of the said regulations,-

- (a) in sub-regulation (6), in the *Explanation*, in clause (b), for the brackets, word and letters "(f) and (g)", the brackets, word and letters "(f), (g) and (h)" shall be substituted.
- (b) after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(7) On and from the 1st day of November, 2017, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.07% of pay.";

7. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) On and from the 1st day of November, 2017,-

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.50 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following Table, namely:-

TABLE

Place of work	House Rent Allowance
(1)	(2)
1. Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	9.0% of pay
2. Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	8.0% of pay
3. Other places	7.0% of pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.50 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above Table.

Note: The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall be also be restricted to 150 per cent. of House Rent Allowance as hitherto."

8. In regulation 23 of the said regulations,-

- (A) for clauses (i) to (v), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(i) on and from the 1st day of November, 2017, if an officer is serving in a place mentioned in column (1) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable.

TABLE

Places	Rate
(1)	(2)
1. Places in Area I and above and in the State of Goa	Rs 1400/- per month
2. Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Rs 1150/- per month;

- (ii) on and from the 1st day of November, 2017, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations;
- (iii) on and from the 1st day of November, 2017, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.600/- per month or Rs.525/- per month according to the classification of area as Group A or Group B, respectively;
- (iv) on and from the 1st day of November, 2020, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs 1650/- per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place;
- (v) on and from the 1st day of November, 2020, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.6000/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place;

Provided that if he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs 3000/- per month:

Provided further that an officer on deputation to the training establishment of the Bank, as a faculty member, shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs.3000 per month.";

- (b) for clause (8), the following clause shall be substituted, namely:-

"(viii) on and from the 1st day of November, 2017, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.300 per month.";

- (c) for clause (10), the following clause shall be substituted, namely:-

"(10) On and from 1st November, 2017, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the Table below, namely:

TABLE

Place	Rate
(1)	(2)
1. Place with an altitude of 1000 meters and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs. 1125/- per month
2. Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1500/- per month
3. Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.3000/- per month";

(d). after clause (10), the following clauses shall be inserted, namely:-

- "(xi) on and from the 1st day of November, 2017, an officer shall be eligible for learning allowance of Rs 600/- per month along with Dearness Allowance thereon;
- (xii) on and from the 1st day of November, 2017, an officer shall be eligible for a fixed allowance of Rs.700/- per month who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance and this fixed allowance shall not be reckoned for payment of Dearness Allowance, superannuation benefits, viz, pension including New Pension Scheme, Provident Fund and gratuity;
- (xiii) from the financial year 2020-21, the Performance Linked Incentive shall be payable to all officers annually based on Operating Profit or Net Profit over and above the normal salary payable, and the Performance Linked Index matrix mentioned in the Table below shall decide the amount payable (in number of days of pay = Basic + Dearness Allowance) depending on the annual performance of the Bank.

TABLE

Sl.No.	Year-over-Year growth in operating profit	Number of days for which Salary (Basic + Dearness Allowance) shall be paid
(1)	(2)	(3)
1.	< 5%	Nil
2.	5% to 10%	5 days
3.	> 10% to 15%	10 days*
4.	> 15%	15 days*
*3 rd and 4 th slabs are payable only if the Bank has Net Profit. If a Bank has growth in operating profit of 5 percent and more, but there is no Net Profit, then minimum 2 nd slab of 5 days shall be payable."		

9. In regulation 24 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) On and from the 1st day of November, 2017, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl.No.	Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	(2)	(3)
1.	Junior Management and Middle Management Grade	Rs.10300/- per annum or the amount incurred whichever is less
2.	Senior Management and Top Executive Grade	Rs.12300/- per annum or the amount incurred whichever is less

Explanation.- For the purpose of this sub-regulation,-

- (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above; or
- (ii) for the year 2017, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, for November, 2017 and December, 2017."

10. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

- "(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2017, a sum equal to 0.50 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.10 per cent. of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer."

11. In regulation 32 of the said regulations, in sub-regulation (2), after the proviso, the following *Explanation* shall be inserted, namely:-

Explanation.- For the purposes of this regulation, it is clarified that –

- (a) casual leave not availed in the year 2017 or any subsequent years shall lapse in the following five year; and
- (b) on and from the 1st November, 2020, the unavailed casual leave by the officer shall be permitted on medical grounds and no medical certificate is required for the period of such unavailed casual leave at a stretch not exceeding four days."

12. In regulation 33 of the said regulations,-

- (a) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

- "(4) on and from the 1st day of June, 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred and seventy days except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of 240 days:

Provided further that from the calendar year 2020, an officer shall also be eligible for encashment of privilege leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an officer who have already completed fifty-five years of age as on 1st January, 2020 and above shall be eligible to encash Privilege Leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement as a one time measure.";

- (b) after sub-regulation (4), the following sub-regulations, shall be inserted, namely:-

"(5) An officer desiring to avail privilege leave shall ordinarily give not less than ten days notice of his intention of avail such leave, except for the purpose of leave fare concession.

(6) When there is no credit in the sick leave account of the officer, privilege leave taken on sick grounds shall not be counted as an occasion of availing privilege leave."

13. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (4), the following regulation shall be inserted, namely:-

"(5) Women officers may avail sick leave for the sickness of their children of eight years and below subject to production of medical certificate."

14. For regulation 35 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"35. Additional sick leave.- (1) On and from the 1st January, 1989, where an officer has put in a service of twenty-four years, he shall be eligible to additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of twenty-four years subject to a maximum of three months of additional sick leave.

- (2) On and from the 1st day of January, 2017, where an officer has put in a service of thirty years, he shall be eligible for further additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of thirty years subject to a maximum of three months of additional sick leave:

Provided that the total number of sick leaves shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer:

Provided further that in case of additional sick leaves availed on or after the 29th June, 1999, commutation of additional leave may be allowed in accordance with sub-regulation (2) of regulation 34."

15. For regulation 36 of the said regulation, the following regulation shall be substituted, namely:-

" 36. Maternity leave.- (1) in case of maternity leave,-

(a) a female employee shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months.

Provided further that maternity leave may be availed combining with any other kind of leave except casual leave;

(b) in case of miscarriage or medical termination of pregnancy or abortion, a female employee may avail maternity leave upto six weeks on the basis of medical certificate or advice of a competent medical practitioner, that is, a qualified gynaecologist and in special or exceptional cases involving medical complications, associated with miscarriage or medical termination of pregnancy or abortion, maternity leave may be availed beyond six weeks, if advised by a qualified gynaecologist, but upto six months only on any one occasion, within the overall limit of twelve months during the entire period of service;

(c) within the overall period of twelve months, leave may also be availed in case of hysterectomy upto a maximum of sixty days.

Note: In the case of employees who have availed and exhausted maternity Leave of twelve months, leave of fifteen days shall be sanctioned over and above the same, subject to production of medical certificate;

(d) a childless female employee may avail leave once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely: -

- (i) leave availed for is for adoption of only one child;
- (ii) the adoption of a child shall be through a proper legal process and the employee shall produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;
- (iii) the permanent part-time employees are also eligible for grant of leave for adoption of a child;
- (iv) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;
- (v) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service;

(e) within the overall period of twelve months, leave may also be availed in case of hospitalisation on account of the following gynaecological ailments or treatments upto a maximum of thirty days, namely:-

- (i) AUB (Abnormal uterine bleeding);
- (ii) Ovarian Tumor;
- (iii) Tubectomy or Tubectomy reversal;
- (iv) Post-Partum Depression (PPD);
- (v) Post-Partum Hemorrhage (PPH);
- (vi) Acute Pelvic Inflammatory Disease (Acute PID);
- (vii) Dysfunction Uterine Bleeding (DUB).

(2) In case of paternity leave, with effect from the 1st June, 2015 male employees with upto two surviving children shall be eligible for fifteen days paternity leave during his wife's confinement and this leave may be combined with any other kind of leave except casual leave:

Provided that the leave may be availed upto fifteen days before or upto six months from the date of delivery of the child.

Provided further that paternity leave as above shall be allowed to a male employee with upto two surviving children for legally adopting a child who is below one year of age."

16. For regulation 37 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"37. Extra-ordinary leave.- (1) An officer shall be eligible for extraordinary leave on loss of pay for not more than twenty-four months during the entire period of service.

(2) An officer may avail extraordinary leave on any one occasion for a period not exceeding three months and in extreme medical circumstances, he may avail extraordinary leave upto four months on any one occasion.

Note : The employee will not be losing any seniority on account of availing extraordinary leave on medical grounds."

17. For regulation 37A of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"37A. Special casual leave and special leave.- (1) With effect from the 1st November 2020, an officer employee shall be eligible for special casual leave on occasions when the branch where the officer is working or the place where he is residing is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, etc.

(2) With effect from the 1st November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days special casual leave.

(3) An officer may also be granted special casual leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time."

18. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(a) Halting Allowance : On and from the 1st day of November 2020, an officer in the grades or scales set out in column (1) of the Table shall be entitled to *per diem* halting allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Grades or Scales of pay of officers	Metro Rs.	Major Class cities 'A' Rs.	Area I Rs.	Other places Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Officers in Scale VI and above	2700	1950	1650	1425
2. Officers in Scale IV and V	2250	1950	1650	1425
3. Officers in Scale I, II and III	1950	1650	1/125	1200:

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, halting allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing halting allowance "per diem" shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, "per diem" shall mean a period of not less than eight hours.'.

19. In regulation 42 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(3) On and from the 1st day of November, 2020, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely: -

TABLE

Grade or Scale	Amount
(1)	(2)
1. Top executive and senior management (officers in scale IV and above)	Rs. 30,000/-
2. Middle management and junior management (officers upto scale III)	Rs. 25,000/-."

20. In regulation 45 of the said regulations, after sub-regulation (4), and before the Note, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that with regard to officers covered under Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), the Bank shall make a contribution of fourteen per cent. of pay plus dearness allowance with effect from the 11th November, 2020:

Provided further that the service charges of the service provider or fund manager of New Pension Scheme shall be borne by the Bank from the financial year 2020-21."

21. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely: -

"Schedule

[See clause (ii) of regulation 23]

With effect from the 1st day of November, 2017, an officer shall be eligible for the special areas allowances till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE**Special Area Allowance**

Sr.No.	Area (State of Union territory)	Allowances (Rs)	
		Pay below Rs.36,000/-	Pay above Rs.36,001/-
		Rs.	Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mizoram		
	(a) Chimgtuipui district and areas beyond 25 kilometers from Lunglei town in Lunglei district.	4000	5200
	(b) entire Lunglei district excluding areas beyond 25 kilometers from Lunglei town.	3200	4200
	(c) entire Aizawl district	2400	3000
2.	Nagaland	3200	4200
3.	Andaman and Nicobar	4000	5200
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands		
	(b) South Andaman (including Port Blair)	3200	4200

4.	Sikkim	4000	5200
5.	Lakshadweep	4000	5200
6.	Assam	640	800
7.	Meghalaya	640	800
8.	Tripura (a) Difficult areas of Tripura	3200	4200
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	2400	3000
9.	Manipur	2400	3000
10.	Arunachal Pradesh (a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	4000	5200
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	3200	4200
11.	Jammu and Kashmir (1) Kathua district: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	4000	5200
	(2) Udhampur district: (a) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b).	4000	5200
	(b) Areas upto Goel from Kamban side and areas upto Arnas from Keasi side in tehsil Mohre.	3200	4200
	(3) Doda district: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar tehsil	4000	5200
	(4) Leh District : all places in the district	4000	5200
	(5) Barmulla district: (a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar sub-division and Keran Illaquas	4000	5200
	(b) Matchill	3200	4200
	(6) Poonch and Rajouri district : areas in Poonch and Rajouri district excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two districts	2400	3000
	(7) Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the state Government for their own staff.	2400	3000
12.	Himachal Pradesh (1) Chamba District (a) Pangi tehsil, Bharmour tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	4000	5200
	(b) Bharmour tehsil, excluding panchayats and villages included in (a) above.	3200	4200
	(c) Jhandru panchayat in Bhatiyat tehsil, Churah tehsil, Dalhousie town (including Banikhet proper).	2400	3000
	(2) Kinnaur district: (a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang panchayats, 15/ 20 Area comprising the gram panchayats	4000	5200

	of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh sub-division, excluding the panchayat areas specified above.		
	(b) entire district other than areas included in (a) above.	3200	4200
	(3) Kullu district: (a) 15/20 Area of Nirmand tehsil, comprising the gram panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	4000	5200
	(b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire district excluding outer Saraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of tehsil Nirmand).	2400	3000
	(4) Lahaul and Spiti district : entire area of Lahaul and Spiti	4000	5200
	(5) Shimla district : (a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	4000	5200
	(b) Dora-Kawar tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath tehsil and Munish, Ghorī Chaibis of Pargana Sarahan.	3200	4200
	(c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghorī Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	2400	3000
	(6) Kangra district: (a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	3200	4200
	(b) Dharamshala town of Kangra district and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugher, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub- Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar	2400	3000
	(7) Mandi district: Chhuvar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gato, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.	2400	3000
	(8) Sirmaur district: Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	2400	3000

	(9) Solan district : Mangal Panchayat.	2400	3000
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.	640	800
13.	Uttar Pradesh: Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts	4000	5200
14.	Uttarakhand: Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat districts	4000	5200
15.	West Bengal South 24 Parganas District Sunderban Areas (South of Dampier Hodge's line), namely, Bhagatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhinga Khali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, Pathar Pratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousioni, Kalinagar, Harao, Hingalganj, Basanti, Kuemari, Kultola, Ghushighata (Kulti)	1000	1000.”.

DILLIP KIUMAR BARIK, General Manager-HR

[ADVT.-III/4/Exty./729/2024-25]

Note: The Indian Overseas Bank (Officers') Service Regulations, 1979 were published in the Gazette of India, subsequently amended *vide* following notifications:-

S No.	Notification Number	Dated	Date of publication in the Official Gazette
1.	31/SUP/97	12.01.1988	13.02.1988
2.	31/SUP/861	07.05.1988	28.05.1988
3.	31/SUP/2139	29.07.1988	22.10.1988
4.	PAD/177/3/88	09.12.1989	30.12.1989
5.	PAD/177/1/89	09.12.1989	30.12.1989
6.	PAD/177	05.03.1994	09.04.1994
7.	PAD/177	21.07.1995	28.10.1995
8.	PAD/177	17.08.1996	09.11.1996
9.	PAD/177	19.11.1996	07.12.1996
10.	PAD/177	12.05.1999	12.06.1999
11.	PAD/SUP/177	09.09.1999	09.10.1999 and 16.10.1999
12.	PAD/SUP/177	22.05.2000	17.06.2000
13.	PAD/SUP/177	28.08.2001	08.09.2001
14.	PAD/SUP/177	29.11.2002	21.12.2002
15.	PAD/SUP/177/49	10.05.2006	08.06.2006

16.	PAD/SUP/177	25.03.2008	05.04.2008
17.	HRMD/SUP/177/001	28.03.2019	08.02.2021
18.	HRMD/SUP/177/002	28.03.2019	08.02.2021
19.	HRMD/SUP/177/01/2021-22	08.02.2022	16.02.2022

EXPLANATORY MEMORANDUM

These regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.